

ई०-मेल

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक:-9/सू०अ० (विविध)-8-285/2026-1724

पटना/दिनांक:-07/9/26

प्रतिलिपि-प्रथम अपीलीय प्राधिकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय)/लोक सूचना पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता-सह-लोक सूचना पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक एवं रूपांकण सहित)-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक एवं रूपांकण सहित)-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।


03/09/26
अधीक्षण अभियंता

-सह-

लोक सूचना पदाधिकारी |

ज्ञापांक:-9/सू०अ० (विविध)-8-285/2026-1724

/पटना/दिनांक-07/9/26

प्रतिलिपि-विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई-मेल तथा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु अनुलग्नक सहित प्रेषित।


03/09/26

अधीक्षण अभियंता

-सह-

लोक सूचना पदाधिकारी |



पत्रांक-21/रा0सू0आ0(न्याय)-11/2022, सा.प्र. 15838/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक स्वरूप अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
01 SEP 2026
सेवा में,
संख्या.....

मो0 आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार
पुलिस महानिदेशक, बिहार।

संयुक्त सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना।

सभी आयोग के सचिव।

बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

बिहार के सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/
क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक।

बिहार के सभी जिला पदाधिकारी।

बिहार के सभी पुलिस अधीक्षक।

बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव।

पटना-15, दिनांक 31.8.26.



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No-990/2021 में पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन के संबंध में।

बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-614, दिनांक-06.08.2026 एवं विभागीय पत्रांक-9032, दिनांक-21.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि

Writ Petition (Civil) No-990/2021 किशन चंद जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 की धारा 4 को राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों में लागू

करने/करवाने हेतु बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-653, दिनांक-22.10.2024,

पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025 एवं पत्रांक-1734, दिनांक-06.03.2026 एवं विभागीय

पत्रांक-9032, दिनांक-21.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। परन्तु अबतक धारा 4 के

अनुपालन में वांछित सूचना का स्वप्रेरण प्रकटन सभी लोक प्राधिकारों (विभाग/सक्षम

प्राधिकार/प्रमंडल/जिला/विश्वविद्यालय आदि) द्वारा नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी लोक प्राधिकारियों को

अधिनियम की धारा-4 के आलोक में, नियमित अंतराल पर संसूचना के विभिन्न साधनों के

माध्यम से (जिसके अंतर्गत इंटरनेट, वेबसाइट आदि भी हैं) सूचना प्रकाशित करने हेतु

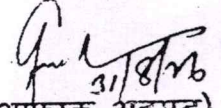
निदेश देने की कृपा की जाय।

कृ०पृ०उ०

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु०-यथोक्त

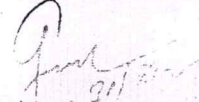
विश्वासभाजन,

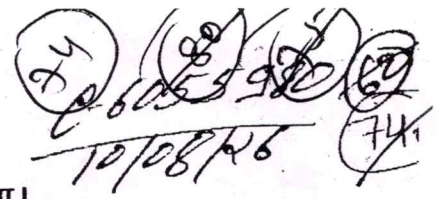

(मो० आफाक अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/रा०सू०आ०(न्याय)-11/2022 सा.प्र.। 5838/पटना-15, दिनांक-31.8.26

प्रतिलिपि- बिहार सूचना आयोग, पटना को उनके पत्रांक-614, दिनांक-06.08.2026 के आलोक में एवं आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।



दिनांक- 06/08/2026

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



पत्रांक-21/रा0सू0आ0(न्याय)-11/2022, सा.प्र.9032/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार
पुलिस महानिदेशक, बिहार।

सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना।

सभी आयोग के सचिव।

बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

बिहार के सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक।

बिहार के सभी जिला पदाधिकारी।

बिहार के सभी पुलिस अधीक्षक।

बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव।

पटना-15, दिनांक 21.5.25

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No-990/2021 में पारित आदेश के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग- बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Writ Petition (Civil) No-990/2021 किशन चंद जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक-17.08.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश पारा-26 एवं 27 निम्न है:-

"reasons stated above, we direct that the Central information Commission and the State Information commissions shall continuously monitor the implementation of the mandates of Section 4 of the Act as also prescribed by the Department of Personnel and Training in its Guidelines and Memorandums issued from time to time. The directions will also include instructions under O.M. dated 07.11.2019 issued by the Department. For this purpose the Commissioners will also be entitled to issue recommendations under sub-Section (5) of Section 25 to public authorities for taking necessary steps for complying with the provisions of the Act."

"The Writ Petitions (C) No. 990 of 2021 is disposed of with the direction to the Central Information Commission and the State Information Commissions to ensure proper implementation of the mandate of Section 4 of the Act, by following the directions as indicated above."

2. उपर्युक्त कार्यकारी अंश में केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को आदेशित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी लोक प्राधिकारों का अधिनियम की धारा-4 के आलोक में, नियमित अंतराल पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से (जिसके अंतर्गत इंटरनेट, वेबसाइट आदि भी हैं) सूचना प्रकाशित करने के लिये निदेश दें, जिससे कि आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम-से-कम सहारा लेना पड़े।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-21/रा०सू०आ०(न्याय)-11/2022 सा.प्र.9032/पटना-15, दिनांक-21.5.25

प्रतिलिपि- बिहार सूचना आयोग, पटना को उनके पत्रांक-196, दिनांक-09.05.2025 के आलोक में एवं आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।